

### प्रेस विज्ञप्ति

माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने, भा.कृ.अनु.प. के उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसन्धान संस्थान, उमियम, जिला री भोई, मेघालय द्वारा आयोजित "उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि मेला 2018" में लोगों को सम्बोधित किया

- मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में कृषि परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त मौका है।
- पारंपरिक खेती के बजाय किसानों द्वारा फसल की चक्रीय खेती, एकीकृत खेती प्रणाली, जैविक खेती, किसानों द्वारा दोहरी / तिहरी फसल प्रणाली लेने से कृषि से उनके मुनाफे में वृद्धि होगी।
- पूर्वोत्तर के राज्यों में मोदी सरकार के पहले कृषि से जुड़े 7 महाविद्यालय थे, अब 13 हो गये। पहले मेघालय में 5 कृषि विज्ञान केन्द्र थे, अब 3 कृषि विज्ञान केन्द्र हो गये हैं।
- मोदी सरकार द्वारा मेघालय को किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की मदद में दी गई राशि के खर्च में तेजी लानी चाहिए।

उमियम, रि भोई, मेघालय: माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने एवं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि कृषि प्रणालियों की वर्तमान स्थिति में सुधार करके, कृषि से आने वाली आय को दोगुना किया जा सके। कृषि मंत्री ने यह बात आज , भा. कृ. अनु. परि. के उमियम स्थित उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसन्धान संस्थान, जिला री भोई, मेघालय द्वारा आयोजित "उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि मेला 2018" में कही

कृषि मंत्री ने कहा कि मेघालय सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बदलते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में कृषि परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त मौका है। लाभदायक एवं स्थान विशेष तकनीकों के द्वारा, निरंतर रोजगार सृजन करने से कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी करने की जरूरत है। राज्य सार्वजनिक, निजी और अन्य हितधारकों में सहयोग, सूचना, प्रौद्योगिकी, ज्ञान और संसाधनों को साझा करके ही आपसी विकास एवं अनमोल प्राकृतिक संसाधनों और समय की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कृषि मंत्री ने विश्वास जताया कि बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बाद ही उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्र में अन्नानास, संतरा, फूलों इत्यादि का अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जा सकता है और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ अधिशेष को बाजार में बेचा जा सकता है जो हस्तक्षेप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पारंपरिक खेती के बजाय किसानों द्वारा फसल की चक्रीय खेती, एकीकृत खेती प्रणाली, जैविक खेती, किसानों द्वारा दोहरी / तिहरी फसल प्रणाली लेने से कृषि से उनके मुनाफे में वृद्धि होगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में, भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने के लिए सरकार ने सिंचाई, स्वाॅयल हेल्थ मनेजमेंट, जैविक खेती से फसल बीमा तक की रणनीति प्रारंभ की है। मेघालय की सरकार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग करना चाहिए। "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए दी गई 50 लाख की राशि चार वर्षों से लंबित है, अभी तक खर्च नहीं कर पाई। जल प्रबंधन एवं जल संचयन के लिए अलग से वर्ष 2015-16 में 1 करोड़ 42 लाख रुपये दी गई, उस वर्ष सरकार खर्च नहीं कर पायी। वर्ष 2016-17 में भी 32 लाख रुपये खर्च नहीं कर पायी और वर्ष 2017-18 में भी इनके पास 2 करोड़ 52 लाख रुपये पड़ा हुआ है अभी तक जो जानकारी है, खर्च की रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं दी गई है। स्वाॅयल हेल्थ कार्ड के लिए वर्ष 2015-17 के बीच मेघालय सरकार को 44 लाख रुपये दिये गये, बताया जा रहा है कि 2 लाख 9 हजार स्वाॅयल हेल्थ कार्ड बांटे गये हैं, इस वर्ष भी 53 लाख रुपये इस काम के लिए दिये गये हैं। जैविक खेती जो मेघालय के किसानों के स्वभाव में है, मोदी सरकार आने के बाद नई योजना चलाई, राज्य को पैसा दिया। वर्ष 2016-17 में दिये गये 1 करोड़ 59 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भारत सरकार को नहीं भेजा है। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम के मिशन के तहत मोदी सरकार ने 4 वर्षों के अंदर जो राशि दी है, उसका भी वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। वर्ष 2016-17 में 57 लाख रुपये ही खर्च किये। वर्ष 2017-18 में डेढ़ करोड़ का आवंटन है, 80 लाख रुपये पहले ही भेज दी गई है। अभी तक खर्च की रिपोर्ट नहीं है, लगता है कि खर्चा नहीं कर पायेंगे व शेष राशि नहीं ले पायेंगे। मैं आज राज्य सरकार से यह कहूंगा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करे।

उन्होंने कहा कि भा. कृ. अनु. परि. का उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसन्धान संस्थान ने इसकी स्थापना के बाद से उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र की कृषि समस्याओं के लिए कई बुनियादी रणनीतिक और

व्यावहारिक अनुसंधान किए हैं। इनमें 32 स्थान विशिष्ट खेती प्रणाली और स्थानांतरण खेती के लिए कृषि वानिकी मॉडल का विकास, 37 चावल किस्मों सहित 56 फसल किस्मों का उत्पादक, उच्च उपज पशुधन और मछली प्रजातियों की पहचान, फसल प्रणाली के आधार पर 32 फसलों के लिए जैविक उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित फसल और बागवानी फसलों के लिए उपजाने की विधि, पशुधन और मछली पालन पद्धतियों और पशुधन संरक्षण उपाय आदि प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। कृषि विकास में कुशल मानव संसाधनों की जरूरतों को देखते हुए पूर्वी राज्यों में स्थापित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल का सशक्तिकरण किया है। पूर्वी राज्यों में मोदी सरकार के आने तक मात्र 7 महाविद्यालय थे, इसी साठे तीन वर्ष के अंदर अब 13 महाविद्यालय हो गये हैं, जिसमें मेघालय के अंदर बड़ापानी में एक बागवानी महाविद्यालय एवं एक कृषि महाविद्यालय स्थापित है। पहले मेघालय में 3 कृषि विज्ञान केन्द्र थे, अब 5 कृषि विज्ञान केन्द्र हो गये हैं।

कृषि मंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में, भा.कृ.अनु.प. के उत्तर पूर्वी पर्वतीय अनुसन्धान संस्थान, उमियम ने अगले 5 वर्षों में अपनाये गये गांवों में पायलट आधार पर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। किसानों को अधिक लाभ मिले, आमदनी बढ़े, इस हेतु किसान कल्याण की कई योजनाएं राज्यों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत सहायता दी जाती है। कृषि मंत्री जी ने मेघालय की सरकार से इन योजनाएं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आह्वान किया है।

\*\*\*



